समक्ष एम.एम पूंछी, जे.

भविष्य निधि निरीक्षक,पानीपत के माध्यम से राज्य- याचिकाकर्ता

बनाम

श्री नारायण सिंह और अन्य- उत्तरदाता

आपराधिक पुनरीक्षण 346/1982

15 नवम्बर 1983

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 204 और 251 - धारा 204 के तहत आदेश पारित करते समय बिना दिमाग का उपयोग किए मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को बुलाया गया - आरोपी उपस्थित हुआ और कथित अपराध का विवरण उसे नहीं बताया गया, मजिस्ट्रेट ने आरोपी को यह कहते हुए आरोप मुक्त कर दिया कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं था - ऐसी प्रक्रिया - क्या कानून में स्वीकार्य है।

माना गया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 204 के तहत आदेश पारित करते समय, मजिस्ट्रेट ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया होता तो उसे उस स्तर पर आरोपी पर संहिता की धारा 251 के तहत आरोप लगाने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार, यह व्यावहारिक रूप से कदमों को पीछे ले जाने जैसा था, एक बार उन्हें आगे ले जाने के बाद: एक ऐसी स्थिति जिसकी अनुमति नहीं थी। मजिस्ट्रेट का आदेश स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करने की प्रकृति का था और इसे अलग रखा जाना चाहिए, लेकिन अलग नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही समन आदेश भी अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। (पैरा 3)

श्री केके डोडा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करनाल की अदालत के 15 जून, 1981 के अभियुक्तों को आरोप मुक्त करने के आदेश के पुनरीक्षण के लिए सीआरपीसी की धारा 397/401 के तहत याचिका।

याचिकाकर्ता के लिए सी. डी. दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस. के. शर्मा, अधिवक्ता के साथ

प्रतिवादी की ओर से डी.एस. बाली, अधिवक्ता, आर.ए. यादव, अधिवक्ता के साथ

निर्णय

मदन मोहन पूंछी, जे.

1. यह निर्णय 1982 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 346,347, 348 और 349 का निपटारा करेगा। ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करनाल के चार संबंधित आदेशों के खिलाफ हैं, जिसके तहत उन्होंने इन मामलों में आरोपियों को तलब करने के बाद, उन पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के तहत आवश्यकतानुसार आरोप नहीं लगाए। प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता भविष्य निधि निरीक्षक होने के नाते, आरोपी के आरोपमुक्त करने के आदेशों पर सवाल उठाते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जो विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए विचार के परिणामस्वरूप पारित किए गए थे।
2. संबंधित फाइलों से यह स्पष्ट है कि, प्रत्येक शिकायत प्राप्त होने पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत कोई आदेश पारित किए बिना, सिर्फ यह आदेश दिया कि अभियुक्त को बुलाया जाए। इसके बाद, अभियुक्त , बुलाए जाने पर, उसके सामने उपस्थित हुए। उस समय, शिकायतकर्ता ने जोर देकर कहा कि आरोप का सार आरोपी को बताया जाए जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के तहत अनिवार्य है, क्योंकि शिकायतकर्ता वैध रूप से आशा कर सकता है कि अभियुक्त अपना दोष स्वीकार कर लेगा। अब, यहां विद्वान मजिस्ट्रेट ने उस पाठ्यक्रम का पालन करने के बजाय, राय दी कि अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं था और यह भी स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अभियुक्त का आपत्तिजनक फर्म के साथ कोई संबंध था या यहां तक कि ऐसी कोई फर्म अस्तित्व में नहीं थी। विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि यह शिकायतकर्ता पर निर्भर है कि वह प्रथम दृष्टया यह स्थापित करने के लिए अदालत के समक्ष कुछ दस्तावेजी सबूत पेश करे कि आपत्तिजनक फर्म अस्तित्व में थी और उसके सामने व्यक्तिगत रूप से आरोपी उसका भागीदार था। शायद यह भी पर्याप्त नहीं था जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14-ए को पढ़ने से स्पष्ट है, जिसमें फर्मों पर आपराधिकता लागू की गई है।

जैसा भी हो, विद्वान मजिस्ट्रेट ने आगे बढ़ने का विकल्प नहीं चुना और आगे बढ़ने से इनकार करने में क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि प्रतीत होती है।

3. जैसा कि पहले बताया गया है, विद्वान मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत आदेश पारित करते समय अपने दिमाग का उपयोग नहीं किया, क्योंकि यदि उसने ऐसा किया होता तो उसे उस स्तर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के तहत आरोपी पर आरोप लगाने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार, यह व्यावहारिक रूप से कदमों को पीछे ले जाने जैसा था, एक बार उन्हें आगे ले जाने के बाद; एक स्थिति जो अस्वीकार्य है । विद्वान मजिस्ट्रेट के आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करने की प्रकृति में हैं। इन्हें इस प्रकार अलग रखा जाना चाहिए और तदनुसार अलग रखा जाना चाहिए लेकिन अलगाव में नहीं। इसके साथ ही सम्मन आदेश को भी रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने, जैसा कि पहले कहा गया था, अपना दिमाग नहीं लगाया। जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, मैं शिकायतों को इस तरह खारिज करने का प्रस्ताव नहीं करता हूं, हालांकि उपरोक्त अधिनियम की धारा 14 और 14-ए के स्पष्ट और संयुक्त पढ़ने पर उस संबंध में कुछ कहा जा सकता है।
4. इस प्रकार, इन पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार कर लिया जाता है, आक्षेपित आदेशों और सम्मन आदेशों को भी रद्द कर दिया जाता है, और शिकायतों को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया जाता है। विद्वान मजिस्ट्रेट को सलाह दी जानी चाहिए कि, हालांकि यह सच है कि जब कोई शिकायत किसी लोक सेवक द्वारा दायर की जाती है, जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का इरादा रखता है, तो उस स्थिति में मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और उसके गवाहों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है; फिर भी इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि शिकायत में दिए गए कथन आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करने को उचित ठहराते हैं। अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को अपनी राय व्यक्त करनी होती है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है और केवल तभी आरोपी को कार्यवाही जारी की जा सकती है। इन्हीं कारणों से शिकायतों को विचारार्थ विद्वान मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजा जा रहा है।
5. शिकायतकर्ता, जो सभी चार मामलों में आम है, को अपने वकील के माध्यम से 13 दिसंबर, 1983 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करनाल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशीष कुमार मंडल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
फिरोज़पुर झिरका, नूंह